सियासी खेल में घटने लगा शुगर बिजनेस का दबदबा

करीब 35 हजार करोड़ रुपये की शुगर इंडस्ट्री यूपी की इकनॉमी के लिए काफी अहम है। यहां के मिलर्स देश में चीनी उत्पादन में लगभग एक तिहाई योगदान करते हैं

[मनमोहन राय *लखनऊ*]

यूपी में यह कोई छिपी बात नहीं है कि चीनी कंपनियां राजनीतिक दलों को जमकर चंदा देती रही हैं। हालांकि अब चीनी मिल मालिकों का कहना है कि प्रदेश की सरकारी नीति उनके खिलाफ जा रही है क्योंकि राजनीतिक दल मिलों की कीमत पर किसानों का समर्थन हासिल करने की होड़ में हैं। प्रदेश में अगले साल लोकसभा के चुनाव होने हैं।

मिलों का कहना है कि सियासी रुख ने उन्हें मुश्किल में डाल दिया है। करीब 100 मिलों ने गन्ना पेराई बंद कर दी है। यूपी सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दे रही है। प्रदेश के एक बड़े मिल मालिक ने कहा कि हम शुगर बिजनेस में पिछले 80 साल से हैं, लेकिन ऐसा बुरा वक्त कभी नहीं देखा था। शटडाउन की नौबत कभी नहीं आई थी।

तनातनी दरअसल गन्ने के राज्य समर्थित मूल्य यानी एसएपी को लेकर है। यह दाम मिलों को किसानों को देना है। दूसरी ओर चीनी की रिटेल प्राइस पर कंट्रोल है। लिहाजा मिलें बढ़ी लागत को कंज्यूमर के सिर नहीं डाल सकतीं। मिल मालिक ने कहा कि यहां से आगे अब हम ऐसे दौर में बढ़ सकते हैं, जब या तो गन्ने की कीमत वाजिब रूप से तय होने लगेगी या शुगर इंडस्ट्री का दम घुट जाएगा।

प्रदेश में करीब 35 हजार करोड़ रुपये की शुगर इंडस्ट्री इसकी इकनॉमी के लिए काफी अहम है। प्रदेश के मिलर्स देश में चीनी उत्पादन में लगभग एक तिहाई योगदान करते हैं। हालांकि यूपी में बदलते राजनीतिक समीकरणों के बीच शुगर इंडस्ट्री के दबदबे में भी बदलाव आया है। इंडियान शुगर मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक मार्च 2013 में खत्म वित्त वर्ष में इंडस्ट्री को लगभग 3 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सुधीर पंवार ने कहा कि ऐसा भी दौर था, जब चीनी मिलें लोकल पॉलिटिक्स को बड़े पैमाने पर प्रभावित करती थीं। खासतौर से वेस्टर्न और सेंट्रल यूपी में एमएलए के इलेक्शन पर उस इलाके की बड़ी चीनी मिल का काफी हद तक प्रभाव पड़ता था। मिलें अपनी पसंद के उम्मीदवारों को खुले हाथों से चंदा देती थीं, ताकि जीतने पर वह एमएलए स्थानीय प्रशासन में उनकी बात मजबूती से रख सकें।

पंवार ने कहा कि हर मिल के लिए शुगरकेन सोसायटी के जरिए यह सब होता था। सोसायटी का हेड कोई किसान होता था, जो करीब 35 किमी. के दायरे में मौजूद दूसरे किसानों का प्रतिनिधि होता था। मिलें अपनी पसंद के उम्मीदवार को शुगरकेन सोसायटी का चेयरमैन बनाने के लिए जोड़-तोड़ करती थीं। उन्होंने कहा कि अक्सर ऐसा देखा गया कि चेयरमैन किसानों के बजाय चीनी मिलों के हितों के लिए काम करता था। लाखों किसानों का प्रतिनिधि होने के कारण वह प्रभावशाली व्यक्ति बन जाता था। मिलों में किसानों का काम उसी के जरिए हो पाता था।

इलाके के गन्ना किसानों के परिवारों की आर्थिक स्थिति में चेयरमैन का दखल बेहद अहम था। मिलों से किसानों को किए जाने वाले भुगतान पर उसी का नियंत्रण होता था। साल 2012-13 के सीजन में शुगर मिलों ने 22 हजार करोड़ रुपये का गन्ना खरीदा था। पंवार ने कहा कि ऐसी कई केन सोसायटियों के चेयरमैन बाद में इतने प्रभावशाली हो गए कि वे एमएलए भी चुने गए। इस समीकरण के चलते मिलों का सरकार के साथ करीबी रिश्ता बन जाता था। बड़ी मिलों के बड़े अफसरों की पहुंच सीएम ऑफिस तक होती थी। इस बिजनेस का आकर्षण ही था कि पुराने परंपरागत कारोबारी घरानों के अलावा पूर्व मंत्री डी पी यादव जैसे लोग और सहारा इंडिया जैसे घराने भी इस कारोबार में उतरे। हालांकि समाज के हाशिए पर पड़े लोगों ने जब अपना रास्ता बनाना शुरू किया, तो पिछले दो दशकों में सियासी तस्वीर बदल गई। इसके अलावा रियल एस्टेट, पावर प्रॉड्यूसर, मेटल एक्सपोर्टर, शराब कारोबारी जैसे कई अन्य स्रोत राजनीतिक चंदे के लिए मिल गए।

Economic Times

2/12/13